भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3602

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात

3602. **सुश्री इकरा चौधरी:**
श्रीमती रुचि वीरा:
श्री देवेश शाक्य:
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री नीरज मौर्य:
श्री लालजी वर्मा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के समाचारों का संज्ञान लिया है, जिनमें यह दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश के दलित एवं पिछड़े समुदाय बहुल क्षेत्रों, विशेषकर सहारनपुर जिले तथा एटा-कासगंज एवं जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय मानकों से कहीं अधिक है, यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा क्या है तथा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए निधियां आवंटित किए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अनेक विद्यालयों में कार्यशालाओं, उपकरणों तथा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों के अभाव के कारण विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो इन कमियों को दूर करने और इस समस्या के हल के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत यूनिफ़ोर्म एवं पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में होने वाले विलंब का विद्यार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों एवं रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने अथवा विद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती,

सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और 25:1 से कम पीटीआर बनाए रखने पर बल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहारनपुर, एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निम्नानुसार है -

क्र. सं.	छात्र शिक्षक अनुपात	राज्य स्तर	एटा	जौनपुर	कासगंज	सहारनपुर
1	प्राथमिक स्तर	19	17	16	21	18
2	उच्च प्राथमिक स्तर	26	19	23	27	23

(ख): समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कौशल शिक्षा प्रदान करने और कक्षा 9 से 12 तक के कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 के स्कूली छात्रों को 138 जॉब रोल (जेआर)/कौशल विषय प्रदान करने का अनुमोदन दिया गया है।

कौशल शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र में उनके व्यावहारिक शिक्षण और प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाया जा सके। वे उद्योग अनुभव और नवीनतम तकनीकों और प्रथाओं के संपर्क में भी आते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एटा जिले के 13 सरकारी माध्यमिक स्कूलों और 7 सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सभी अनुमोदित स्कूलों में व्यावसायिक प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध हैं, और व्यापार-वार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। छात्रों को इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक विजिट में भाग लेने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी/आईटीईएस), बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई), ओर्गनाइस्ड रीटेल, कृषि, विद्युत, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, सौंदर्य और कल्याण, पर्यटन, मोटर वाहन, सुरक्षा, और परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग सहित क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की पेशकश की जाती है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कासगंज जिले के 13 सरकारी माध्यमिक स्कूलों और 7 सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यान्वित की जा रही है। सभी 13 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध हैं और सभी अनुमोदित स्कूलों में ट्रेड-वार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम के तहत नामांकित छात्रों को गेस्ट लेक्चर में भाग लेने और उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में औद्योगिक विजिट में भाग लेने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में

सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस), संगठित खुदरा, प्रबंधन और उद्यमिता

और पेशेवर कौशल, कृषि, विद्युत, सौंदर्य और कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, मोटर वाहन और परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग सहित कई व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं।

(ग): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से पात्र छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है। इन लाभों के प्रावधान में कोई देरी नहीं हुई है। राज्य सरकार पात्रता के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए समय पर धनराशि जारी करने और उपयोग सहित योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

(घ): जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पना की गई है, केंद्र सरकार ने बुनियादी स्तरों से रोजगार योग्यता, श्रम की गरिमा और कार्य संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल/व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), एनईपी 2020 के साथ संरेखित, शैक्षणिक विषयों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रत्यक्ष रूप से मध्य और माध्यमिक चरणों में एकीकृत करके कौशल शिक्षा को संस्थागत बनाती है। सामान्य शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा का एकीकरण महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता, समस्या-समाधान, जीवन कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है, इस प्रकार बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। इस एकीकरण का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परियोजना-आधारित शिक्षा के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान से सुसज्जित करना है। छात्र यह सीखेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग विभिन्न व्यवसायों में क्या करते हैं और भविष्य के करियर की संभावनाओं से अवगत होंगे, जिससे शिक्षा के माध्यम से स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में जौनपुर जिले में 7 सरकारी माध्यमिक स्कूलों और 40 सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी/आईटीईएस), बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई), ओर्गनाइस्ड रीटेल, पर्यटन, मोटर वाहन, सुरक्षा, परिधान, और मेड-अप और होम फर्निशिंग सहित कई क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

*****